श्री वीरेन्द्र वर्मा : बड़े उद्योग वाले।

श्री सत्य पाल मलिक : बडे उद्योग वाले करते हैं। इसके अलावा स्वयं जो आपके बिजली बोर्ड हैं उसके बारे में बहुत दिनों से बहस चल रही है कि उनको चलाने वाले टैक्नीकल लोग हों या आफिसर लोग हों। वहां पर आई०ए०एस० लोग बैठ जाते हैं। इसी तरह राज्य में बिजली मंत्रालय किसी स्टेट मिनिस्टर को दे दिया जाता है और 6 महीने के बाद उसको बदल दिया जाता है। अगर वहां पर किसी कम्पीटेन्ट मिनिस्टर को रखा जाय तो वह बिजली बोर्ड के आदमियों पर ठीक से अंकुश लगा सकता है लेकिन इसके अभाव में ऐसा नही हो पाता। इसी प्रकार इसके और बहुत से कारण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अरण्य-रोदन कई सालों से चल रहा है और इस बीच एक खतरनाक बात यह हो गई है कि हम ताप बिजली घरों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गये हैं और यह एक ऐसा विसियस सर्किल है कि कोयला नही है, कोयले की हड़ताल है, उसके लिये वैगन नहीं मिलते हैं, रेल वाले कहते हैं कि वैगन इसलिये नहीं क्योंकि बिजली और डीजल नहीं है और पूरी तरह से यह एक दुश्चक्र चला हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिजली की मांग और पूर्ति में जो फर्क है, जो देश की जरूरत है और देश में उसका जितना उत्पादन होता है इन दोनों में जो फर्क है इसके मिटाने के लिये हाइडल से जो बिजली पैदा करने के सोर्सेज हैं उन को टैप करने के लिये, उनका इस्तेमाल करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, पहले जो माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की है उसका मैं निराकरण करना चाहूंगी। यह केवल किसानों को जिस दर पर बिजली दी जा रही है उसके कारण ही यह सारा घाटा नहीं है। पर यह भी इसका एक मुख्य मुद्दा है। साथ ही साथ जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंटस को एग्रीकल्चर के लिये सब्सीडी देनी चाहिए और जो मांडेटरी है, वर्ल्ड बैंक के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार वह समय समय पर नहीं दे रहे हैं। अगर कम से कम यह रुपया भी हमारी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जाय तो उन्हें अपना काम सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग मिल सकता है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि कोयले के ऊपर निर्भर होने के बजाय पन बिजली के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इस चीज को बड़े ध्यान से देख रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पानी से बिजली उत्पन्न कर सकें। मान्यवर, आज हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उससे 84 हजार मेगावाट बिजली हम केवल पानी से उत्पन्न कर सकते है लेकिन आज हम केवल 12 प्रतिशत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना के बाद वह बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाय यह हमारा प्रयास है। पानी से बिजली पैदा करने के लिये आपने देखा है कि बड़ी योजना टिहरी में आगे बढ़ रही है जो कि 24 सौ मेगावाट की है और छोटी छोटी भी बन रही है। हमें आशा है कि यह कार्य भविष्य में और आगे बढ़ता चला जायेगा।

*467. [*The questioner (Shri Ajit P.K. Jogi) was absent. For answer, vide col.* 37-38 infra.]

*468. [*The questioner (Shri Satya Prakash Malaviya) was absent. For answer,* vide *col.* 38—43 infra.]

*469. [*The questioners (Shri Lal K. Advani and Shri Ashwani Kumar) were absent. For answer,* vide *col.* 43—45 infra.]

Uniform Power Tariff for Agricultural Sector

*470. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:†
SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Central Government has recently issued any direc-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra Singh Hanspal.

tions to the State Governments to ensure a uniform power tariff for the agricultural sector throughout the country;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued and what is the reaction of the State Governments in regard thereto; and

(c) whether it is a fact that several State Elecricity Boards are suffering losses due to variations in power tariff?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A number of factors, including low tariffs for certain categories of consumers, contribute to the losses incurred by several State Electricity Boards.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मंत्री महोदया ने ए और बी सवाल के जवाब में यह कह दिया कि ऐसा नहीं हो रहा है । लेकिन एक रिपोर्ट है "हिन्दुस्तान टाइम्स" 7 मार्च, 1988 की "uniform power tariff to farms mooted" बहुत बड़ी रिपोर्ट है । तो क्या मंत्री महोदया के ध्यान में यह रिपोर्ट नही आई है । अगर आई है तो फिर इसका जवाब "नो" कैसे हो गया, यह मैं जानना चाहूगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, ध्यान मे आना एक चीज है और डाइरेक्शन इश्यू करने में थोड़ा सा फर्क है । बहुत सी चीजें ध्यान मे रखकर कोई निर्णय लेते हुए डाइरेक्शंस इश्यू किये जाते है । जैसा कि आपने कह दिया whether we have recently issued any directions,
उसके साथ हमने कहा "नो सर" साथ ही साथ यह जरूर है कि इस पर काफी गम्भीरता से विचार किया जाये और कोई निर्णय या काम सारे पहलुओं से विचार विमर्श कर सबको ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : ठीक है । सवाल में डाइरेक्शन लफ्ज मुझे नहीं लिखना चाहिये था तब शायद ज्यादा इन्फारमेशन मिलती... (**व्यवधान**) यह मेरी गलती है । मैंने सवाल लिखा इसलिये मेरी गलती है । फिर भी इससे पहले के क्वेश्चन में बहुत डिसक्शन हुआ कि ये लासेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को क्यों होते है । जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सरकार या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स यह कहते है कि 60 पैसे पर यूनिट एग्रीकल्चर को जो आप बिजली देते है उसेस लासेज होते है । क्या यह सही है ? और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लासेज जो हो रहे हैं उसके अन्य सदस्य ने भी बहुत से कारण बताये जैसे ओवर स्टाफिंग है, लो जेनरेशन आदि । आपने भी माना है कि हाई ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन लासेज है और चोरी भी एक कारण हैं । इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह है कि 20 परसेंट आफ दी आपरेशनल कास्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस को तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है ताकि यह बर्डन उनके ऊपर से उतर जाये और खास तौर से एग्रीकल्चर को और इन्डस्ट्री को भी सस्ते दामों में बिजली दी जा सके ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सही है कि इन्टरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के कारण काफी गरीब 20 प्रतिशत बोझा डालता है इसलिये जैसे अभी पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पिछले माह या इसी माह इसमें और इसके पहले भी व्यक्तिगत रूप से स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के मिनिस्टर्स को मैंने लिखा था कि इस बर गम्भीरता से विचार किया जाये और यह आदेश जा चुके है कि इस चीज को कैपिटलाइज कर दिय जाये । इसके अतिरिक्त जो सभी ने कहा कि हमारे बीच में काफी कमियां है तो उन सभी कमियों को गौर से देख रहे हैं कि कैसे ओवर स्टाफिंग, इनइफीशियंसी में सुधार हो सकता है, मेंटिनेस, रिनोवेशन

माडर्नाइजेशन और ज्यादा जनरेशन इन सारी चीजों को वाकायदा से देख रहे हैं । साथ ही साथ इतना भी मुझे कहना पड़ेगा कि सन् 1950 से 1987 के बीच

while the total sales of electricity have increased by 33 times, the sales to the agricultural sector have increased by 174 times.

यह अपनी पालिसी है कि कृषि के क्षेत्र में सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी बिजली हम लोग उनको दे सकें । सूखे के दौरान इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ी है और उसमें हमने टारगेट से ज्यादा काम किया है, उसको पूरा किया है जैसे आर० इ० सी० के बारे में बताया गया है और इसके अलावा दोनों जगह इलैक्ट्रिफिकेशन और एनर्जाइजेशन में अपने लक्ष्य से ज्यादा काम किया है । घाटा तो बढ़ता ही जाता है पर साथ में और भी कारण हैं ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैंने यह पूछा था कि 60 पैसे पर यूनिट एग्रीकल्चर को आप देते है तो क्या इसकी सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट्स देती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बहुत अच्छा प्रश्न है । देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पर कुछ एकाध ही दे रहे होंगे, सब नहीं दे रहे हैं पर उनको देना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि देश में गन्ना, गेहूं, चावल और जितनी भी पैदावार है उन सबकी एक कीमत केन्द्रीय सरकार देश भर में मुकर्रर करती है जबकि कुछ सूखे क्षेत्र मैं हैं, कुछ सिंचित हैं कैनाल्स से, कुछ सिंचित हैं बिजली के ट्यूबवेल्स से कुछ सिंचित हैं डीजल आयल से । सबके क्षेत्र अलग-अलग होते हुए भी एक कीमत मुकर्रर हो जाती है । आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया "जी नहीं" इसलिये चाहे डिफरेंस सोर्सेज है उत्पादन के तो फिर सारे देश में फसल की भांति एक ही कीमत या एक ही रेट मुकर्रर करने मे आपको क्या कठिनाई है ?

ऊर्जा और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : क्योंकि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अलग-अलग राज्यों के है, उनके अलग अलग टैरिफ हैं । उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है । यह राज्यों का विषय है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Objections against Formation of National Power Grid

*461. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1977 given in the Rajya Sabha on the 14th March, 1988 and state:

(a) whether any objections were raised by any State Government against the formation of a National Power Grid; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) No objection was raised by any State Government against the formation of a National Power Grid during the Power Ministers' Conference held in February, 1988.

Waiting list for Maruti-800 cars

*465. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total number of persons still waiting for the allotment of Maruti-800 ordinary car from the Maruti Udyog Limited, throughout the country;